

चुनाव आयोग

लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने छह राज्यों के गृह सचिवों और पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटा दिया है। सूत्रों ने बताया है कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के गृह सचिव को हटाया गया है। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक प्रभाग के सचिवों का भी तबादला कर दिया गया है। इस बीच, चुनाव आयोग के आदेशों के बाद आई.ए.एस. अधिकारी अभिषेक जैन से गृह और विजिलेंस विभाग वापस ले लिए हैं।

बागी विधायक

प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा है। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने और इन विधायकों को वोट देने या सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बागी विधायकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में राहत पाने के लिए दायर याचिका की आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। उल्लेखनीय है कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विषय का उल्लंघन करने पर कांग्रेस के 6 विधायकों, सुधीर शर्मा, राजेन्द्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेन्द्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा की सदस्यता रद्द कर दी थी। विषय जारी होने के बावजूद ये विधायक सदन में बजट पारित होने के दौरान उपस्थित नहीं हुए थे जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष ने इन पर कार्रवाई की थी।

कांग्रेस मंथन

लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। भाजपा ने जहां चार लोकसभा सीटों में से दो पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी आज नई दिल्ली में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करेगी। कांग्रेस पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू भी भाग लेंगे। इसके अलावा प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव को लेकर भी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली रवाना होने से पहले प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी।

प्रिविलेज कमेटी

प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन से निलंबित हुए भाजपा के नौ विधायक प्रिविलेज कमेटी के नोटिस पर आज विधानसभा में पेश हुए। इस दौरान भाजपा विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि बीते बजट सत्र के दौरान सदन की अवमानना के लिए विभिन्न धाराओं में भाजपा विधायकों को प्रिविलेज कमेटी ने नोटिस दिए थे जिस पर आज उन्होंने अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि नोटिस में जो भी उनसे पूछा गया था उस पर उन्होंने विस्तृत रूप से नियमों के अनुसार अपना पक्ष विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रख दिया है। विपिन सिंह परमार ने कहा कि सदन विधानसभा के निर्देशों के अनुसार चलता है और वे अध्यक्ष का मान-सम्मान करते हैं ऐसे में अब विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का इंतजार है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2032 तक इसे देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ जो वायदे किए थे, सरकार उनको पूरा करने के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी अधिकतर चुनावी गारंटियां पूरी कर दी हैं जबकि बाकी भी जल्द ही धरातल पर होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आय के अतिरिक्त संसाधन जुटाने और युवाओं के लिए रोज़गार व स्वरोज़गार के साधन सृजित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

जागरुकता कार्यक्रम

हमीरपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय भोरंज में भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरुकता कार्यक्रम 'स्वीप' के तहत आज एक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर एस.डी.एम व भोरंज के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संजय कुमार ने छात्र-छात्राओं को चुनावी प्रक्रिया के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं से लोकसभा चुनाव 2024 में बढ़-चढ़ कर भागीदारी करने का आव्हान किया, ताकि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत पिछले चुनावों की अपेक्षा अधिक हो।

कार्यशाला

प्रदेश के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा पर मंथन को लेकर दो दिवसीय कार्यशाला आज शिमला में शुरू हुई। कार्यशाला का शुभारम्भ शिक्षा विभाग के सचिव राकेश कंवर ने किया। कार्यशाला में व्यावसायिक शिक्षा की चुनौतियों के साथ ही पर्यटन व आतिथ्य, दूरसंचार, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल, कृषि और प्राइवेट सिक्योरिटी क्षेत्रों में संभावनाओं पर मंथन किया जा रहा है। राज्य समग्र शिक्षा परियोजना के निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश के एक हजार 2 सौ 74 सीनियर सैकंडरी स्कूलों के करीब 95 हजार विद्यार्थियों को 16 ट्रेड में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
